POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2022/अंक 12

मासिक प्रेषण दि. 8 दिसम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 दिसम्बर, 2022 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में केंद्र और राज्य से जुड़ी 19 बड़ी योजनाएं हैं, जो सीधे प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि इनका फायदा जरूरतमंद को कितना मिलता है?

दरअसल, योजनाओं की क्रियान्विति के दौरान ऐसा कोई आंतरिक निगरानी तंत्र नहीं होता जो बजटीय आवंटन, धन के दुरुपयोग व जवाबदेही आदि को अधिकारिक रूप से संभाले। अक्सर 'ग्राम गदर' के माध्यम से यह बात उठाई जाती रही है।

पिछले दिनों राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव ने इन योजनाओं में गड़बड़ी रोकने और सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। विभाग के अधिकारियों को अब हर महीने जिलों में जाकर योजनाओं का जमीनी स्तर जांचना होगा। उन्हें विकास कार्यों का पुनः परीक्षण करने के साथ ही क्रियान्वयन में सामने आई समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी देने होंगे।

विभाग में तैनात राज्य स्तरीय अधिकारियों को इस काम के लिए जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों की जिला स्तर पर समीक्षा बैठक, क्षेत्र भ्रमण आदि समेत समस्त व्यवस्थाओं का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के जिम्मे है। विभाग द्वारा उठाया गया यह कदम स्वागत योग्य है, बशर्ते इसके पीछे सरकार की सकारात्मक इच्छाशक्ति हो।

सरकार मंत्रियों-अधिकारियों से मिलकर बनती है। अक्सर सामने आता है कि ये जिम्मेदार ही अपने दायित्वों से कन्नी काटते हैं। सरकार की जिम्मेदारी तो यह है कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। निगरानी ऐसी हो कि जनता के धन का लाभ अपात्र लोग न उठा पाएं।

डॉ. जय कुमार भाटी 'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित

'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते रहे हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है।

इस बार वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार 'कट्स' द्वारा 'ग्रीन एक्शन वीक'-2022 के तहत जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर श्रीमती मुनेश गुर्जर द्वारा डॉ. जय कुमार भाटी को प्रशस्ति पत्र एवं 10 हजार रुपए का चैक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

डॉ. जय कुमार भाटी जोधपुर जिले में स्थित पावटा के मूल निवासी हैं तथा प्रतिष्ठित हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण में कार्यरत हैं। उन्होंने वर्ष 2021 के दौरान 'विकास में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी' विषय पर कई रोचक स्टोरियां प्रकाशित कर आमजन में जागरूकता लाने एवं जनचेतना जागृत करने का काम किया है।

डॉ. भाटी ने पत्रकारिता व फोटो जर्नलिज्म के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहित कई राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उन्हें फोटो जर्नलिज्म में अन्तर्राष्ट्रीय जीपीयू गोल्ड मेडल मिला है।

भारी पड़ा किसान क्रेडिट कार्ड खाते में पैसा लेकर जमा नहीं करना

राजस्थान के चूरू जिले के साहवा गांव निवासी किसान रामस्वरूप माली ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साहवा शाखा में 8 दिसंबर, 2017 को 54 हजार रुपए अपने किसान क्रेडिट कार्ड में जमा करने के लिए बैंक के कैशियर को सुपुर्द कर जमा की स्लिप प्राप्त की। लेकिन उनके खाते में यह राशि तीन वर्ष तक जमा नहीं हुई। जागरूक किसान रामस्वरूप माली ने जिला उपभोक्ता आयोग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साहवा शाखा के विरुद्ध परिवाद दायर कर यह सारी जानकारी प्रमाण सहित प्रस्तुत की।

जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी होने के बाद विपक्षी बैंक द्वारा फरवरी 2021 में यह राशि परिवादी रामस्वरूप के अन्य खाते में जमा कर दी गई। मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने अपने निर्णय में राशि लेने के बावजूद उनके किसान क्रेडिट कार्ड खाते में जमा नहीं होना विपक्षी बैंक की सेवा में घोर कमी व गलती मानी। आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साहवा शाखा को आदेश दिया कि वह रामस्वरूप माली को उक्त राशि पर तीन वर्ष की अवधि का ब्याज और क्षतिपूर्ति स्वरूप 10,000 रुपए अदा करें।

'ग्रीन एक्शन वीक' अभियान के तहत राज्य स्तरीय परिचर्चा आयोजित

शेयरिंग की भावना को बढ़ाने के साथ ही जागरूकता के लिए महिलाओं को आगे आना होगा

हमारे समाज में शेयरिंग की भावना को पुनः स्थापित करने के लिए जागरूकता लाने के साथ-साथ महिलाओं को आगे आना होगा, क्योंकि महिलाएं ही समाज में बदलाव ला सकती है। उक्त विचार 'कट्स' द्वारा 'ग्रीन एक्शन वीक' के अन्तर्गत आयोजित राज्य स्तरीय परिचर्चा में जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर श्रीमती मुनेश गुर्जर ने व्यक्त किए।

उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान बताया कि जिस कचरे को हम कचरा समझते हैं उसी में से 'कबाड़ से जुगाड़' के माध्यम से 'कट्स' और इनकी सहयोगी संस्थाओं ने इतने अच्छे उत्पाद बनाए हैं, जो कि प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि हमें शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के सह-निदेशक दीपक सक्सेना ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बताया कि 'ग्रीन एक्शन वीक' अन्तरराष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जो कि सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन, स्वीडन के सहयोग से वैश्विक स्तर पर आयोजित किया जाता है।

इस अवसर पर 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि सतत् उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'कट्स' द्वारा इस अभियान को राजस्थान के अलावा भारत के 14 अलग-अलग राज्यों में भी संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के अभियान का मुख्य मुद्दा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रदूषण है। उन्होंने कहा कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग करते हुए सतत् उपभोग को बढ़ावा देना होगा। कार्यक्रम में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के रीजनल ऑफीसर विजय शर्मा ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए आमजन को जागरूक होना होगा।

राजस्थान विश्व विद्यालय की होम साईंस विभाग की प्रोफेसर डॉ. निमाली सिंह ने बताया कि गांवों में आज भी वस्तुओं और सेवाओं को साझा करने की प्रवृत्ति है, इसे शहरी क्षेत्रों में भी फिर से बढ़ावा देना होगा। इस अवसर पर किचन गार्डन, 'कबाड़ से जुगाड़' प्रशिक्षण से जुड़ी महिलाओं ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया गया।

'ग्रीन एक्शन वीक' अभियान की कार्यक्रम अधिकारी निमिषा शर्मा ने अभियान के तहत अब तक की गई गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम अधिकारी राजदीप पारीक ने कार्यक्रम का संचालन किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश अव्वल

राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में अव्वल है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक यहां 88 फीसदी लोग स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं। यहां हर 10 में से लगभग 9 लोग किसी न किसी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेते हैं।

प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा कवरेज के मामले में शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति ज्यादा बेहतर है। ग्रामीण इलाकों की 42 फीसदी आबादी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रही है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 42 करोड़ लोग स्वास्थ्य बीमा सुविधा से वंचित है। ऐसे में बीमा कंपनियों का 2030 तक पूरी आबादी को आरोग्य बीमा के दायरे में लाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य बीमा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इलाज का खर्च बोझ नहीं बनता।

जैविक खाद से गोपालक होंगे स्वावलंबी

प्रदेश की गोशालाओं में गोपालक गोबर से जैविक खाद तैयार करेंगे। यह खाद पैकिंग होकर देश-विदेशों में निर्यात की जा सकेंगी। भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ द्वारा गोशालाओं और गोपालकों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए आर्थिक कार्यक्रम संचालित किया गया है।

संघ के चेयरमैन डॉ.अतुल गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में 400 गोशालाओं को चयनित किया गया है। इनमें गोपालकों को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। गोबर से बनी जैविक खाद की देश-विदेश में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। खाद की गुणवत्ता और पैकेजिंग को ध्यान में रखते हुए उत्पाद का व्यवसायीकरण किया जाएगा, जिससे गोशालाओं और गोपालकों को उत्पाद की सही कीमत मिल सकेगी।

महिला किसान उपजा रहीं है जैविक अन्न

राजस्थान की महिलाएं अब माटी से अन्न निपजाकर देश दुनिया का पेट भर रही हैं। राज्य में खेतों से अन्न उपजाने में महिलाओं की संख्या पुरूषों से ज्यादा हैं। खास बात यह है कि अब राजस्थान की महिला किसान अंगूठा छाप नहीं बल्कि खेती में नवाचार कर रहीं हैं। यहीं नहीं, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी हो रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन महिला किसानों से सीधे जैविक उत्पाद खरीद रही है। जिससे उनकी आय में काफी इजाफा हो रहा हैं।

रंग ला रहा है 'भविष्य की उड़ान' कैंपेन

सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में सवाई माधोपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की पहल से जिले के ग्रामीण समुदाय में बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा है। उन्होंने गांवों के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के स्तर को लेकर, टॉयलेट, कमरों की स्थिति और मैदान आदि के विकास के लिए 'भविष्य की उड़ान' कैंपेन शुरू किया। लोगों को समझाया गया कि बच्चों की पढ़ाई से गांव ही नहीं परिवार का भी नाम होगा।

ग्रामीणों में बच्चों की शिक्षा के प्रति सोच बढ़ी और उन्होंने स्कूल के विकास के लिए पैसा देना शुरू किया तो 6 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। उन्होंने इस फंड से स्कूल का विकास करने का जिम्मा भी गांव वालों पर ही छोड़ा है। अब तक सवा सौ से ज्यादा गांव उनके इस कैंपेन से जुड़ चुके हैं।

राज्य वृक्ष पर चल रही कुल्हाड़ी

प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कंपनियां राज्य वृक्ष खेजड़ी की बेतहाशा कटाई करा रही है। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों के नजदीकी क्षेत्रों में 2000 से भी ज्यादा खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं। इससे प्रदेश की बेशकीमती संपदा और पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

राजस्थान वृक्षों की रक्षा के लिए प्राणों की आहूति देने वाला प्रदेश है। विभागों की अनदेखी के चलते गुपचुप में कंपनियां रात को डीजल, एसिड से खेजड़ी पर स्प्रे करवाती हैं ताकि पेड़ सूख जाए, बाद में एसीबी से उन्हें उखाड़ा जा रहा है। बताया गया है कि खेजड़ी के पेड़ों की गिनती कर वन विभाग को इसकी रिपोर्ट भी सौंपी गई थी, बावजूद इसके रेगिस्तानी वन संपदा पर कुल्हाड़ी चल रही है।

अच्छी बारिश के बावजूद पानी पैंदे में

प्रदेश में इस साल अच्छी बारिश होने के बाद भी भूजल स्तर एक से दो मीटर तक गिरा है। इसका खास कारण भूजल रिचार्ज के मुकाबले जमीन से पानी का दोहन 151.07 प्रतिशत ज्यादा होना है। राजस्थान सहित सभी राज्यों के भूजल स्तर पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड निगरानी करता है।

प्रदेश के 302 में से 219 ब्लॉक भूजल का बहुत ज्यादा दोहन होने के कारण अतिदोहित (डार्क जोन) में आ गए हैं। चिंताजनक यह है कि प्रदेश में केवल 38 ब्लॉक ही सुरक्षित स्थिति में बचे हैं। प्रदेश में इस साल भूजल 12.13 बीसीएम (अरब घन मीटर) रिचार्ज हुआ है। जबकि 16.56 बीसीएम पानी खेती, पेयजल व औद्योगिक उपयोग के लिए जमीन से निकाला गया।

बेटियों को है साइकिल का इंतजार

सरकार ने नौवीं कक्षा की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की घोषणा कर रखी है। लेकिन राज्य की करीब साढ़े तीन लाख बेटियों को स्कूल खुलने के चार महीने बाद भी साइकिल नहीं मिली है। इससे उन्हें पैदल ही स्कूल जाना पड़ रहा है। खासतौर पर गांवों में पढ़ने वाली बालिकाओं को स्कूल तक लम्बी दूरी पार करना उनके लिए बड़ी समस्या बन रही है।

इस बार बेटियों को साइकिल की जगह ई-वाउचर दिया जाना है। इससे वें नजदीकी वेंडर से साइकिल ले सकेंगी। लेकिन उन्हें शिक्षा विभाग की लेटलतीफी का खामियाजा उठाना पड़ रहा है।

कृषि व्यवसाय में निदेशक मंडल निभा रहा है अपनी सक्रिय भूमिका

मेहनती किसान उत्पादक संगठन सेवर, भरतपुर के अध्यक्ष और निदेशक मंडल के सदस्य एफ.पी.ओ. के माध्यम से कृषि व्यवसाय में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अध्यक्ष लाल सिंह ने बताया कि सही समय पर निदेशक मंडल की बैठक और कृषक हित समूह (एफ.आई.जी.) के माध्यम से लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप उचित मूल्य पर सदस्य किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराए गए हैं।

एफ.पी.ओ.से जुड़े 'कट्स' जयपुर और भरतपुर के कार्यकर्ताओं और किसानों के सम्मिलित प्रयासों से एफ.पी.ओ. ने मात्र 6 माह में करीब 30 लाख रुपए का व्यवसाय किया। लाल सिंह का कहना है कि एफ.पी.ओ.के माध्यम से कृषक अब व्यापार करना भी सीख रहे हैं। आने वाले समय में निदेशक मंडल, एफ.पी.ओ. के माध्यम से कृषक उपज का व्यापार करते हुए, किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहयोग करेगा।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485